प्रादेशिक समाचार बुलेटिन,
आकाशवाणी, लखनऊ।

प्रसारण तिथि : 15.09.2025 प्रसारण समय : 19:20 बजे

मुख्य समाचार :–

1. प्रदेश में खुलेगा बायो टेक्नोलॉजी पार्क और साइंस म्यूजियम : सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन समारोह में केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेन्द्र सिंह ने की घोषणा।
2. सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार : वक्फ बनाने के लिए 5 वर्ष तक इस्लाम का पालन करने वाले खंड समेत वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर लगाई रोक।
3. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में हुए शामिल : कहा– सरकार की प्राथमिकता है काशी का विकास। और
4. लखनऊ सहित कई जिलों में मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत : अगले 24 घंटों में प्रदेशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान।

————————

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में

वैज्ञानिक और औद्यानिक अनुसंधान परिषद के स्टार्टअप कांक्लेव के समापन समारोह मे भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसाय के लिए सुरक्षा, सुगमता और मजबूत इको सिस्टम जरूरी है और यह तीनों आज उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज का युग तकनीकी का युग है जो भी देश अनुसंधान और तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी होता है दुनिया उसके पीछे चलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में स्थित सीएसआईआर के चारों संस्थान अपने अनुसंधान से देश औऱ प्रदेश के किसानों और समाज को नई दिशा दिखा रहे हैं। बाइट.....

आज का समय, टेक्नोलॉजी का समय है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमे जितना अधिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, दनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा।और ये हमारा सौभाग्य है। सीएसआईआर की चार महत्वपूर्ण लैब्स NBRI सीडीआरआई, आईटीआर और सी मैप ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए काफी संभावनाएं हैं जिन्हें सही दिशा दिखाकर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बायो

टेक्नोलॉजी पार्क और साइंस म्यूजियम खोले जाने की भी घोषणा की। बाइट.....

आज भारत वर्ष में जो बी टाउन है, जो छोटे कस्बे है वहाँ पर आकांक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है, एस्पिरेशनल लेवल बहुत ऊँचा है। लगभग पचास प्रतिशत हमारे स्टार्टअप टायर टू और टायर थ्री सिटी से आ रहे हैं। जिस तरह से आपने स्टॉल्स देखे होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका काफी अधिक पोटेंशियल है। मेरी कल्पना है कि जिस तरह से हैदराबाद विकसित हुआ है दक्षिण भारत में उसी तरह का पोटेंशियल और क्षमता लखनऊ में है। क्योंकि इतने सारे संस्थान है यहाँ पर की आज तक खोजा नहीं गया तलाशा नहीं किया।

———————————

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया है। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बनाने से पहले पांच साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता वाले खंड पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यह खंड तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस शर्त के निर्धारण के संबंध में कोई समुचित नियम नहीं बना लेती हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि पूरे कानून पर रोक लगान का कोई मामला नहीं बनता है।

सरकार ने नामित अधिकारी को यह निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई है, कि क्या कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करती है। क्योंकि यह शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन होगा। वक्फ बोर्ड में गैर–मुस्लिम सदस्यों के नामांकन को अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। न्यायालय ने कहा है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का पदेन सदस्य मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से अधिक गैर–मुस्लिम सदस्य नहीं होगे और राज्य वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर–मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।

————————————

सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला – सेवा पर्व में, हम आज बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने नमामि गंगे अभियान के माध्यम से हमारी पवित्र गंगा का कायाकल्प किया ह।

भारत की जीवन रेखा गंगा नदी पवित्र, शाश्वत और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अनमोल धारा है। मोदी सरकार द्वारा जून 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे अभियान, इसको मल और उदारपूर्ण नदी के स्वास्थ्य को बहाल करने की एक महत्वाकांक्षी और समग्र पहल है।

नमामि गंगे एक बहुआयामी अभियान है जो प्रदूषण निवारण, पारिस्थितिक पुर्नउत्थान, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करता है। यह नदी की पर्यावरणीय अखंडता और उस पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका, दोनों पर केंद्रित है। इस अभियान ने प्रदूषण निवारण में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीवेज उपचार क्षमता 2014 के बाद से

30 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। गंगा डॉल्फ़िन की जनसंख्या में वृद्धि नदी की पारिस्थिकी तंत्र में सुधार का प्रमाण है। लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहीपवित्र गंगा अब नई आशा के साथ बह रही है, जहां आस्था और दृ ढसंकल्प दोनों कामिलन हो रहा है। विष्णु के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

———————

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

ताज़ा समाचार जानने के लिये आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन ए0आई0आर0 डॉट जी0ओ0वी0 डॉट आई0एन0 पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

———————

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति–दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ज़िले के विकास कार्यों पर संतोष जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाराणसी का विकास केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बाइट.....

बहुत अच्छी चर्चा हुई, जो सरकारी स्कीम्स हैं, परियोजनाएं हैं उनका रिव्यू किया गया और उनकी रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा हुई। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो कलीग्स हैं सांसद, ऑनरेबल मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट,

एमएलए राज्य सरकार के मंत्री लोग उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसमें भाग लिया। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए।

————————————

वस्तु और सेवाकर परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दीं। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार ने दो हजार 500 रुपये से कम मूल्य के जूते–चप्पलों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है, जो पहले 12 प्रतिशत की श्रेणी में थी। कांच की मूर्तियां, लोहे, एल्युमीनियम, पीतल और तांबे से बनी कलाकृतियों परभी इसी तरह की कटौती की गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर विशेषज्ञ टी सुरेश ने कहा कि इन सुधारों का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

————————————

महराजगंज दौरे पर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इस वर्ष सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन 14 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल संस्कृति को गांव–गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी क्रम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन पंचायत स्तर से शुरू होकर ब्लॉक, विधानसभा और लोकसभा स्तर तक किया जा रहा है। बाइट.....

दुनिया में अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित तौर से सभी क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना होगा और उसमें खेल भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और खेल के माध्यम से हमारे बहुत से खिलाड़ी देश और दुनिया में नाम कर चुके हैं। ओलंपिक भी खेल चुके हैं। उसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारे गाँव के भी प्रतिभागी इसमें भाग लें और उनकी प्रतिभा को देखते हुए आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अवसर प्रदान किया जा सके।

———————————

बरेली में आज लेफ्टिनेंट जनरल डी. जी. मिश्रा ने कुमांऊ कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार रैली पिथौरागढ़ आदि कैलाश सहित उत्तराखंड के दुर्गम रास्तों और ग्रामीण अंचलों से होते हुए 22 सितम्बर को वापस बरेली में समाप्त होगी।

———————————

रूक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बलिया में गंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रहीहैं। बलिया, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी समेत प्रदेश के 19 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं लखनऊ सहित कई जिलों में आज सुबह से ही मौसम बदलने और रिमझिम बारिश्स से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

(समाप्त)